प्रो. रामदेव भंडारी:कृपा करके एलाऊ करें, सर।

श्री सभापति : कृपा करने की जरूरत नहीं है। आप बोलना चाहें तो मैं इजाजत दे दूंगा, लेकिन सरला जी बहुत कुछ कह चुकी हैं और जवाब भी अच्छी तरह से मिल गया है।

श्री दत्ता मेघे :सर, वर्धा के बारे में जानना चाहता हूं।

श्री सभापति : नही, नहीं। यह वर्धा के बारे में नहीं है।

प्रो. राम देव भंडारी : सर, मेरा एक ही सवाल है।

श्री सभापति : ठीक है, आप कर लीजिए।

प्रो. राम देव भंडारी : सभापति जी, हमारे जो राजदूत हैं विदेशों में, वे वहां किस प्रकार की भाषा का प्रयोग होता करते है? वहां हिंदी का प्रयोग होता है या नहीं होता है? मैं यह विदेश मंत्री जी से जानना चाहता हूं। क्योंकि मेरा जो अनुभव है उसके हिसाब से वहां बिल्कुल हिंदी का प्रयोग नहीं होता, जो हमारे राजदूत हैं वे हिंदी का प्रयोग नहीं करते।

श्री दिग्विजय सिंह :सभापति जी, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है और कई माननीय सदस्यों ने इसके बारे में चिंता व्यक्त की है कि हिंदी को जो प्राथमिकता मिलनी चाहिए राजभाषा के रूप में, वह देश में तो क्या देश में भी नहीं मिल रही है। इसके लिए पूरा सदन चिंतित है और इसलिए हम भंडारी जी से इतना ही कहना चाहेंगे कि हमारे जो राजदूत हैं उनका प्रयास होता है कि वे हिंदी का भी उपयोग कर सकें, लेकिन उनकी अपनी कुछ मजबूरी हैं क्योंकि जो माहौल है और जिस महौल में वे काम कर रहे है। हमारे यहां राजदूत रहे डा. कर्ण सिंह जी बैठे हुए हैं, इन्होने जितना वहां जाकर हिंदी में काम किया है, उतना किसी ने नहीं किया होगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि आदमी-आदमी पर भी यह निर्भर करता है, लेकिन हमारी तरफ से, सरकार की तरफ से यह प्रयास होता है कि भरतीय भाषाओं का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल हो

Amendment of Central Motor Vehicles rules

*402. MAULANA OBAIDULLAH KHAN AZMI: Will the Minister of ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS be pleased to state:

(a) Whether it is a fact that Government are proposing to amend the Central Motor Vehicles rules again to facilitate alternative technology without the safeguards prescribed by the Apex Committee;

(b) whether Government intend to introduce a monopoly of foreign technology in the transport sector; and

(c) if not, what effective steps are being taken to prevent the State Governments from introducing the monopoly technology?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS (MAJOR GENERAL (RETD.) B.C. KHANDURI): (a) to (c) A statement is laid on the Table of the House.

(b) No, Sir. The proposed amendment of Central Motor Vehicles Rules, which is under examination, merely seeks to prescribe in detail the minimum specifications for Smart Card based driving licence and registration certificate for motor vehicles.

(b) No, Sir.

(c) The Government has developed software specifications for the issue of Smart Card based driving licences and registration certificates for motor vehicles. Standarized software formats, common specifications to be adopted by all the States, the working document for operating system based on ISO-7816 standards and development of application software to be operated on terminals and hand held readers have already been circulated to all the States/ UTs free of cost. The Smart Card Operating System Standards are kept in open domain and are not proprietary standards. This is to prevent monopoly of technology.

† मौलाना ओबैदुल्लाह खान आजमी : चेयरमैन सर, मैने जो सवाल किया है उसका सरकार जिस तरह से जवाब दिया है, मैं यह कहना चाहता हूं कि अपेक्स कमेटी अपनी रिपोर्ट में यह कहा है कि एकाधिकार वाली तकनीक को ड्रायविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के एरिए में शमिल नहीं किया जाएगा। तो मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या इस तरमीम के जरिए आप ऑप्टीकल तकनीक को परमिट करने जा रहे है? जबकि सबको मालूम है कि यह ताकनीक अमरीकन कंपनी पेंटेंटेड है।

مولانا عبیداللہ خان اعظمی : چیئرمین سر، میں نے جو سوال کیا ہے اس کا سرکار نے جس طرح جواب دیا ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ " اپیکس کمیٹی" نے اپنی رپورٹ میں یہ کہا ہے کہ ایکادھیکار والی تکنیک کو ڈرائیونگ لائسنس اور رجسٹریشن سرٹیفکیٹ کے ایریے میں شامل نہیں کیا جائے گا- تومیں منتری مہودے سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا اس ترمیم کے ذریعہ آپ آپٹیکل تکنیک کوپرمٹ کرنے جارہے ہین؟ جبکہ سب کومعلوم ہے کہ یہ تکنیک امریکن پینٹڈ ہے-

† Transliteration of Urdu speech.

मेजर जनरल (सेवा निवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूरी :माननीय सभापति जी, मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि एकाधिकार की किसी भी प्रकार की व्यवस्था को हमने न तो स्वीकृति दी है और न ही देनी है। नोटिफिकेशन में बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि ओपेन डोमेन के अंदर **जो** भी टेक्नोलीजी होगी वहीं इसतेमाल होगी। ओपेन डोमेन का मतलब है कि वह टेक्नोलोजी किसी भी जगह से, कहीं से भी आप डाऊन लोड कर सकते है, कहीं से भी आप ले सकते है, उसके ऊपर कोई पेटेंट नहीं है। नोटिफिकेशन में यह बात बहुत स्पष्ट कर दी गई है। जहां तक आपके प्रश्न का दूसरा भाग है कि यह जो कंपनी है उसको यह अधिकार दे दिया गया है या नहीं **दिया गया** है, इसके लिए यह स्पष्ट कर दिया गया है कि जो भी टेक्नोलाजी कोई लेना चाहें तो वह टेक्नोलोजी ओपेन डोमेन में होनी चाहिए। किसी भी प्रकार के एकाधिकार की व्यवस्था को हमारी तरफ से इजाजत नहीं दी गई है।

† **मौलाना ओबैदुल्लाह खान आजमी** :चेयरमेन सर, मैं इसी सिलसिले में यह बात कहना चाहूंगा कि विदेशी कंपनियों को काम दिया जाता है, स्वदेशीं कपंनियां रह जाती हैं, इससे बेरोजगार अपने लोग होते है। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि जो भी काम दिया जाएगा वह स्वदेशी कंपनियों को दिया जाएगा विदेशी कपंनियों को नहीं दिया जाएगा ताकि हिन्दुस्तानी रोजगार से लगे रहें? मेरा दूसरा भाग ,

مولانا عبیداللہ خان اعظمی: چیئرمین سر، میں اس سلسلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ودیشی کمپنیوں کو کام دیا جاتا ہے، سودیشی کمپنیاں رہ جاتی ہیں اس سے اپنے لوگ بیروزگار ہوتے ہیں، کیا سرکار اس بات کویقینی بنائے گی کہ جوبھی کام دیا جائے گا وہ سودیشی کمپنیوں کودیا جائیگا، ودیشی کمپنیوں کونہیں دیا جائے گا تا کہ ہندوستانی روزگار سے لگے رہیں-

श्री सभापति : बस, हो गया।

† **मौलाना ओबैदुल्ला खान आजमी** : सर, दूसरा सप्लीमेंटरी मेरा बाकी है।

مولانا عبیداللہ خان اعظمی: سر، سپلیمنٹری میرا باقی ہے-

श्री सभापित :हो गया, क्वैश्चन तो एक ही एलाऊ है।

† **मौलाना ओबैदुल्ला खान आजमी** :सर मेरा " बी" पार्ट यह है कि जो तरमीम लाने जा रहे हैं, इसका नोट ही बहुत खतरनाक है। **यह** अधिकार अमरीकन कंपनी के लिए रास्ता साफ करता है। तो क्या इस नोट को हटाकर विदेशी कंपनियों को रोजगार

† Transliteration of Urdu speech.

देने के बजाय स्वदेशी कंपनियों को ऊपर उठाया जाएगा और यह गांरटी दी जाएगी कि विदेशी कपंनियों को नहीं देंगे, सिर्फ हिन्दुसतानी कंपनियों को देंगे?

مولانا عبیداللہ خان اعظمی: سر، میرا 'بی" پارٹ یہ ہے کہ جوترمیم لانے جارہے ہیں، اس کا نوٹ ہی بہت خطرناک ہے- یہ اختیار امریکن کمپنی کے لئے راستہ صاف کرتا ہے- توکیا اس نوٹ کوہٹا کر ودیشی کمپنیوں کوروزگار دینے کے بجائے سودیشی کمپنیوں کواوپر اٹھایا جائے گا اوریہ گارنٹی دی جائے گی کہ ودیشی کمپنیوں کونہیں دینگے، صرف ہندوستانی کمپنیوں کوہی دیں گے؟

मेजर जनरल (सेवा निवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूरी :सभापति जी, मैं माननीय सदस्य की भावनाओं से सहमत हूं कि हमको स्वदेशी लोगों की कंपनियों की टेक्नोलोजी को ज्यादा प्रोत्साहित करना चाहिए, लेकिन मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारे मंत्रालय और केन्द्र का काम नार्मस ले-डाऊन करना है, किसी कंपनी को काम देना नहीं है। यह पूरा का पूरा अधिकार प्रदेश सरकारों का है। हम लोगों ने नोटिफिकेशन में कुछ शर्ते लगाई है।

Cancellation of Passports in UP

*403. SHRI ABU ASIM AZMI: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government are aware that a large number of persons belonging to the minority communities from UP in general and from Azamgarh District in particular have been served with show cause notices about the cancellation of their passports by the Passport Office at Lucknow;

(b) if so, the number of persons who have been issued such notices along with the details of the allegation against each; and

(c) the number of passports which have been cancelled during the last six months?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI VINOD KHANNA): (a) and (b) No, Sir. Show cause notices were issued to all those passport holders whose passports were issued by Regional Passport Office (RPO) LUCKNOW on overdue basis pending paolice verification reports and subsequently adverse/incomplete police verification reports were receive. RPO LUCKNOW had served these notices to all concerned passport holders of its jurisdiction in UTTAR PRADESH irrespective of region